17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के समापन सत्र में माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

आज सहकारिता महा-सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले आप सभी महानुभावों ने इन दो दिनों में सहकारिता के माध्यम से देश में सामाजिक -आर्थिक परिवर्तन लाने के विषय पर गहन विचार विमर्श किया है। सामूहिकता के साथ मिलकर किस तरीके से हम सहकारिता के क्षेत्र में नई तकनीक, अपनी दक्षता और कार्यकुशलता को बेहतर करते हुए 'सहकार से समृद्धि की ओर' बढ़ सकते हैं, आपने इस पर चिंतन किया होगा।

सहकारिता की भावना हमारे मूल स्वभाव में है, हमारे चिंतन में है, हमारे व्यवहार में है। हमारा जो जीवंत लोकतंत्र है, हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का विचार और कार्य शैली सहकारिता पर आधारित है जिसमें हम साथ मिलकर चलते हैं और सामूहिकता के साथ आगे बढ़ते हैं।

सहकारिता का भाव हमारे राष्ट्र-नायकों की सोच में रहा है। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन सहकारिता का एक उत्तम उदाहरण है, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, क्षेत्र और समूह के व्यक्ति ने भागीदारी की।

कई दशक पहले पूरे विश्व में और भारत में सहकारिता आंदोलन का जो युग शुरू हुआ, तो उससे देश के सभी संकटों का समाधान संभव हुआ है। चाहे रोजगार का संकट हो, कृषि का संकट हो, उपभोक्ताओं का संकट हो, ऋण का संकट हो, उद्योगों का संकट हो, उत्पादन का संकट हो, खाद्य आपूर्ति का संकट हो, या अर्थव्यवस्था का संकट हो, ऐसे हर संकट का समाधान करने में सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

एक समय था, जब कृषि मुनाफे का काम नहीं होता था। किसान फसल उगाता था, तो उसको अपनी उपज का मूल्य भी नहीं मिल पाता था। जितनी लागत लगती थी, वह लागत भी नहीं निकल पाती थी। क्योंकि तब ऊंची ब्याज दर पर किसान को ऋण लेना पड़ता था, अपनी फसल गिरवी रखनी पड़ती थी। उन्हें फसल लागत से कम दाम पर बेचनी पड़ती थी। इसके

परिणामस्वरूप हमारा किसान लगातार कर्ज में डूबा रहता था और उस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाता था।

लेकिन सहकारिता आंदोलन से किसान और मजदूरों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। आज किसानों को सहकारिता के माध्यम से एक से डेढ़ लाख रुपये का ऋण ज़ीरो प्रतिशत ब्याज दर पर मिलना संभव हुआ है। साथ ही किसानों को सहकारी समितियों से खाद, बीज और उर्वरक सस्ते दर पर मिल रहे हैं।

हम सबने वह समय भी देखा है, जब देश में युद्ध के समय उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य चरम पर चले गए थे, उस समय उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से लोगों को नियंत्रित दामों पर राशन और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराईं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की।

जब देश के आम आदमी के लिए मकान मिलने मुश्किल होते थे, महंगे दर पर मकान मिलते थे, तब हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी। इस तरह मैं आपको ऐसे कई सेक्टर्स के उदाहरण दे सकता हूँ, जिन सेक्टर्स के अंदर कॉपरेटिव्स के माध्यम से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ।

मेरे पास कई सहकारी समितियों के उदाहरण हैं, जहां पर आपस में छोटी मोटी पूंजी जमा करके, महिलाओं ने अपनी बचत जमा करके ऐसे समूह बनाए हैं जिनमें जरूरत के समय समूह के सदस्यों को कम ब्याज दर पर पैसा मिलता है।

देश के गाँव कस्बों में ऐसे अनगिनत समूह हैं, जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की रचनात्मक भूमिका को आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है।

मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हमारी सहकारी समितियां आज मेक इन इंडिया के विजन को साकार कर रही है। सहकारिता सेक्टर हमारे देश का निर्यात बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है।

सहकारिता मॉडल पर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अमूल और आनंद डेयरी की चर्चा आज विश्व स्तर पर हो रही है कि किस प्रकार इन्होंने डेयरी किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश में श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया।

आज 25 हजार से ज्यादा सहकारी समितियां फिशरीज सेक्टर में काम कर रही हैं जिनके कारण नील क्रांति का युग आया है। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर आज मछली पालन करने वाले छोटे किसान भी फिश प्रोसेसिंग, फिश ड्राइंग, फिश स्टोरिंग, फिश स्टोरेज, फिश कैनिंग, फिश ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक काम संगठित तरीके से कर रहे हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है, उनका जीवन बेहतर हुआ है।

ऐसा भी एक समय आया, जब सहकारिता के क्षेत्र में करप्शन, प्रबंधन, पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे। लेकिन, पिछले कुछ समय में जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने सहकारिता क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए हैं, उससे सहकारिता के स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है।

प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के 75 सालों के बाद सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है, जिसमें पारदर्शिता और आधुनिकता लाने के लिए अब हम पैक्स का कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं।

आज सहकारिता में हम टेक्नॉलजी का उपयोग कर रहे हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाले हैं। इससे निश्चित रूप से हमारी सहकारी संस्थायें और बेहतर तरीक़े से चलायी जायेंगी।

सहकारिता के क्षेत्र में आज जो नीतियाँ तैयार की जा रही हैं, उनसे गाँव के अंदर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए काम होगा, इस क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेज अपनाने की कार्यवाही की जा रही है। हर ग्राम पंचायत पर पैक्स बने, इसके लिए कार्ययोजना बन रही है।

इन सबके साथ यदि हमने सहकारिता में अपनी दक्षता को, कार्यकुशलता को, पारदर्शिता को और प्रबंधन व्यवस्था को और बेहतर कर लिया, तो मेरा विश्वास है कि इस देश में आर्थिक परिवर्तन का नया युग शुरू होगा, तो सहकारिता के माध्यम से ही होगा।

इस अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध होगा, तो सहकारिता के माध्यम से ही होगा। देश के गाँव और किसान की शक्ति को बढ़ाने के लिए सहकार और सरकार को साथ मिलकर काम करना होगा।

सहकारिता की भावना के साथ हम कोई भी काम करेंगे, सोसाइटी में मिलकर काम करेंगे, सामूहिकता के साथ काम करेंगे; तो हर सेक्टर के अंदर हम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं।

आज यह आवश्यक है कि सहकारी सेक्टर पारदर्शिता का, जवाबदेही का और करप्शन रहित गवर्नेंस का मॉडल बने; ताकि देश के सामान्य नागरिक का कोआपरेटिव्स पर भरोसा और अधिक मजबूत हो।

सहकारिता जैसे सामाजिक संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क सामाजिक पूंजी में वृद्धि करने में मदद करता है और सामाजिक पूंजी जितनी अधिक होगी, विकास की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी।

यह हमारा कर्तव्य है कि हम सहकारिता को लेकर जागरूकता को बढ़ाएं। देश के गांवों में किसान मिलकर आपसी सहकार से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करें, कोल्ड स्टोरेज चेन की स्थापना करें, ताकि गांवों में फल-सब्जी और फसल की प्रोसेसिंग और भंडारण किया जा सके तथा गाँव में रोजगार का सृजन हो।

मुझे विश्वास है कि नए भारत में सहकारिता देश की आर्थिक धारा का सशक्त माध्यम बनेगी। जब हम अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब भारत की उन्नति और विकास में सहकारिता सेक्टर की सबसे बड़ी भूमिका होगी।

सहकारिता को अधिक समृद्ध बनाने के लिए हमें इस भाव के साथ आगे बढ़ना होगा कि सहकार सिर्फ आर्थिक उद्यम नहीं है, यह संस्कार है। सहकारी समितियों में सहयोग करने वालों की भूमिका ट्रस्टी के रूप में होनी चाहिए, मालिक की नहीं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महा-सम्मेलन में इन दो दिनों का यह विमर्श हमारे देश में सहकारिता आंदोलन और इसकी भावना को और अधिक मजबूत बनाएगा। कोआपरेटिव में भी कोऑपरेशन को और बेहतर कैसे बनाएं, हम इस ध्येय को लेकर आगे बढ़ेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि कॉपरेटिव्स को राजनीति की बजाए समाज नीति और राष्ट्रनीति का वाहक बनना चाहिए। यह हमारा मूलमंत्र होना चाहिए।

इसी संदेश के साथ मैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) को इस महा-सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके प्रयासों से आने वाले समय में सहकारिता भारत के विकास इंजन की एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी कड़ी साबित होंगी। आप सभी को अनेक शुभकामनाएं।